

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 30 अगस्त, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय केदारनाथ, जनपद रुद्रप्रयाग में जन शौचालय के भवन निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-74/1/बदे चिकि०/27/2005/6860 दिनांक 08.03.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006-07 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय केदारनाथ, जनपद रुद्रप्रयाग में जन शौचालय के निर्माण हेतु रु० 41,50,000.00 (रु० इकतालीस लाख पचास हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य हेतु रु० 41,50,000.00 (रु० इकतालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

3- कार्य कराने समय लो० नि० विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा ।

4- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तत्पश्चात् निर्माण इकाई परियोजना प्रबंधक, राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- आगणन में उल्लेखित दरों को विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हों, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

7- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

8- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

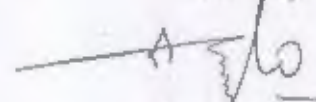
A

सं० 698(1)/XXVIII-5-2006-15/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/ कुमाऊं मण्डल, उत्तरांचल ।
- 3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल ।
- 4- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 6- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तरांचल ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 9- निजी सचिव मा० मुख्यमंत्री ।
- 10- परियोजना प्रबन्धक, उपरो राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 11- वजेट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून ।
- 12- वित्त(व्यय नियंत्रण) / नियोजन विभाग / एन०आर०सी० अनुभाग-3 ।
- 13- गार्ड फाईल ।

आज्ञा सी,



(अतर सिंह)

उप सचिव

- 9- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।
- 10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भू-भाग निरीक्षण ठेकेदारों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाये
- 11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
- 12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है
- 13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी ।
- 14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।
- 15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।
- 16- जी०पी०डब्ल्यू० आर्न १ की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।
- 17- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक संख्या-2047Xiv-219(2006) देहरादून दिनांक 30.05.2006 में दिये गये निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाये, पालन न करने पर निर्माण इकाई इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होगी ।
- 18- उक्त व्यय वर्ष 2006-07 के आय-व्यय में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-निकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पुंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-आयोजनगत, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 17-अनावासीय भवनों में वृहत स्तरीय अनुदान विस्तारीकरण तथा निर्माण, -00- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।
- 19- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०-520/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ 2006 दिनांक 24.8.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अतर सिंह)

उप सचिव